



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2009/चैत्र 11, 1931

No. 140]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2009/CHAITRA 11, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** यूरोपीय संघ, सिंगापुर, कोरिया गण. और यूएसए के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्रोपीलीन ग्लाइकोल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/26/2008-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ, सिंगापुर, कोरिया गण. और यूएसए (जिन्हें आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्रोपीलीन ग्लाइकोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर दिनांक 8 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 105/2004-सी.शु. के तहत मूल रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था

## 2. विचाराधीन उत्पाद

मूल मामले में विचाराधीन उत्पाद प्रोपीलीन ग्लाइकोल-समस्त ग्रेड था (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) । इस निर्णायक समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित रहता है । ग्लाइकोल का विनिर्माण उच्च ताप और दाब पर जल के साथ प्रोपीलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है । प्रोपीलीन ग्लाइकोल का उपयोग पॉलिस्टर रेजिन के विनिर्माण, औद्योगिक प्रशीतनरोधी अनुप्रयोगों जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों तथा भेषज उद्योगों में किया जाता है । यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ कोड 29053200 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

## 3. जाँच की शुरुआत

इण्डियन मेटल एण्ड फेरो एलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 2006 की 16893 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा प्रवृत्त शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करते हैं ।

#### 4. शामिल देश/क्षेत्र

इस जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, सिंगापुर, कोरिया गण. और यूएसए हैं।

#### 5. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 (12 माह) है। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं जांच अवधि शामिल हैं।

#### 6. प्रक्रिया

20 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. 14/8/2003-डीजीएडी के तहत जारी अंतिम जांच परिणाम तथा 8 अक्टूबर, 2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 105/2004 के तहत लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्रवृत्त शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देशों/क्षेत्र के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जांच शुरू करते हैं। इस समीक्षा में 20 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. 14/8/2003-डीजीएडी (मूल जाँच का अंतिम जाँच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं।

#### 7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों/क्षेत्र के निर्यातकों, भारत में दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधिक कार्यालय के जरिए संबद्ध देशों/क्षेत्र की सरकारों, भारत में इस उत्पाद के संबंधित समझे जाने वाले आयातकों तथा प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप में तथा तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने हेतु अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं :—

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य विभाग  
कमरा नं. 240, उद्योग भवन,  
नई दिल्ली-110001

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित प्रारूप में तथा तरीके से इस जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

#### 8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई संबंधी अनुरोध लिखित में भिजवाया जाए, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

#### 9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे। अगोपनीय रूपांतरण या गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना के बारे में सार्थक जानकारी उपलब्ध हो सके। यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश व्यवहार्य नहीं है तो उसके कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसका सामान्यीकृत रूप में या सारांश रूप में प्रकटन करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है तो ऐसी सूचना की अनेदखी की जा सकती है।

#### 10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

#### 11. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2009

**(SUNSET REVIEW)**

**Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed against Propylene Glycol originating in or exported from the European Union, Singapore, Korea RP and USA.**

**No. 15/26/2008-DGAD.**— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed *vide* notification No. 105/2004-Customs, dated the 8th October 2004 on import of Propylene Glycol (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from the European Union, Singapore, Korea RP and USA (hereinafter referred to as the subject countries/territory).

**2. Product under consideration**

The product under consideration in the original case was Propylene Glycol—all grades (also referred to as the subject goods). The product under consideration remains unchanged for the purposes of this sunset review investigation. The propylene glycol is manufactured by the reaction of the propylene oxide with water at high temperature and pressure. The Propylene Glycol is used for industrial applications like manufacture of polyester resin, industrial anti-freezing applications and in pharmaceutical industries. This product is classified under Customs Tariffs Code 29053200.

**3. Initiation**

In view of the order of the Hon'ble Delhi High Court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd. V/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**4. Countries/territory involved**

The countries/territory involved in this investigation are the European Union, Singapore, Korea RP and USA.

**5. Period of Investigation**

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April 2008 to 31st March, 2009, (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2005-06, 2006-07, 2007-08 and POI. The data beyond POI may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

**6. Procedure**

Having decided to review the final findings issued *vide* Notification No. 14/8/2003-DGAD dated 20th August, 2004 and final duty imposed *vide* Customs Notification No 105/2004 dated 8th October, 2004, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether cessation of Anti-Dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of Dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject countries/territory in accordance with the Act and the AD Rules. The review covers all aspects of Notification No. 14/8/2003-DGAD, dated 20th August, 2004 (final findings of the original investigation).

**7. Submission of Information :**

The exporters in subject countries/territory, the governments of subject country/territory through its embassies/ High Commission/ Representative office in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India  
Ministry of Commerce and Industry  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Department of Commerce  
Room No.240, Udyog Bhavan,  
New Delhi-110001.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### **8. Time Limit**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

#### **9. Submission of information on Non-confidential basis**

All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules supra. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reasons thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

#### **10. Inspection of public file**

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

#### **11. Non-cooperation**

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority